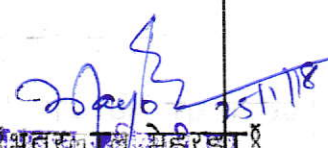


दिनांक	आज्ञा पत्र
25.1.2018	<p>अपील दर्ज रजिस्टर हो । मियाद का बिन्दू रिजर्व रहेगा । स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया । वकील अपीलान्ट के बहस में कथन किया कि अदालत मातहत में रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 नानूराम ने अदालत मातहत प्रार्थना पत्र धारा-212 राज० कार्रकारी अधिनियम का गलत आधारों पर पेश किया है । आराजी ख० नं० 1053 रकबा 0.1300 हेक्टर एवं ख० नं० 1049/1 रकबा 0.3000 हेक्टर में रेस्पोंड को कोई लेना देना नहीं है। अपील के साथ मैंने जमाबन्दी पेश की है। अदालत मातहत ने बिना राजस्व रेकार्ड को अवलोकन किये ही केवल कहने मात्र से ही मुझे एक रेकार्डेड खातेदार कार्रकार को स्थगन आदेश से पाबन्द करने का आदेश विधि विरुद्ध पारित कर दिया । इसके बाद जब एकपक्षीय आदेश 5-10-17 को पारित कर दिया तो अदालत मातहत को इस आदेश को 30 दिन में अन्तिम रूप से निष्पत्ति करना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने इस आदेश को बिना किसी कारण के आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है । विवादित आराजी का अपीलान्ट रेकार्डेड खातेदार कार्रकार है जिसके विरुद्ध पारित अन्तरिम आदेश को स्थगित किया जावे ।</p> <p>बहस बगौर समाप्त की गई । प्रार्थना पत्र एवं राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी का अवलोकन किया गया । जमाबन्दी सं०- 2070 से 2073 में अन्य खातेदारों के साथ रेस्पोंडेन्ट सं०- नानूराम 0.15 हेक्टर का सहखातेदार दर्ज है । ख० नं० 1053 एवं 1049/1 में तो नानूराम का कोई हिस्सा नहीं है इन दोनों खसरा नम्बरों पर स्थगन आदेश पारित कर एक रेकार्डेड खातेदार कार्रकार को विधि के विपरित पाबन्द</p>

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	<p>किया गया है। खसरा नं० 1052 में नानूराम केवल सहखातेदार है। एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार को पाबन्द नहीं करवा सकता क्योंकि सहखातेदार का तो प्रत्येक इंच पर कब्जा माना गया है। अदालत मातहत को अपने एकपक्षीय आदेश को 30 दिन में निर्णित करना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने इस एकपक्षीय आदेश को बिना किसी कारण के आगे की पेशगी तक बढ़ाया है। जिसको हम उचित नहीं मानते हैं। अतः अपीलान्ट की अपील को इसी स्तर पर स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक दांतारामगढ का निर्णय दि० 5-10-2017 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये प्रार्थना पत्र का निस्तारण 30 दिन में पारित करे। पक्षकार अदालत मातहत में नियत पेशगी पर उपस्थित होवे।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  अवसर की मेडर डा भू-सूचना अधिकारी/अधिकारी पदेन राजस्व अपीकरण अधिकारी सीकर </p>	